प्रसार भारती
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
18.11.2025 / प्रादेशिक समाचार / 9:20बजे

''आज के मुख्य समाचार''

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य सरकारों से बेहतर निवेश वातावरण बनाने और विकास मानकों को आगे बढ़ाने में प्रतिस्पर्धा करने का किया आह्वान।
- प्रधानमंत्री कल 19 नवंबर को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त करेंगे जारी।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहाड़ी राज्यों की बढ़ती संवेदनशीलता को देखते हुए आपदा राहत नियमों की समीक्षा करने का केंद्र से किया आग्रह।
- राज्य सरकार ने सरकारी भूमि को लीज पर देने की अवधि 99 से घटाकर 40 वर्ष की।
  और
- प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली मनाली–लेह सड़क 20 नवंबर से आधिकारिक तौर पर वाहनों के लिए होगी बंद।

प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी राज्य सरकारों से बेहतर निवेश वातावरण बनाने, व्यापार सुगमता में सुधार लाने और विकास मानकों को आगे बढ़ाने में प्रतिस्पर्धा करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में छठे रामनाथ गोयनका व्याख्यान में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे प्रयासों से जनता का विश्वास अर्जित होगा। नरेन्द्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय विकास के लिए सभी लोगों तक लाभ पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता उन राजनीतिक दलों पर भरोसा करती है जो उनकी अकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ईमानदारी से काम करते हैं।

सम्मान निधि

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल 19 नवंबर को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के साथ इस योजना के अंतर्गत देशभर के 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को तीन लाख 70 हजार करोड़ रूपए से अधिक की राशि सीधे खाते में भेजी जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस योजना में किसान परिवारों को सालाना 6 हजार रूपए दिये जाते हैं जो दुनिया के सबसे बड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कार्यक्रमों में से एक है।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केंद्र से पहाड़ी राज्यों की बढ़ती संवेदनशीलता को देखते हुए आपदा राहत नियमों की समीक्षा करने और आपदा प्रबंधन मानदंडों में उचित संशोधन का आग्रह किया है। हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लेते हुए उन्होंने जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृति और नुकसान को देखते हुए पूरे उत्तरी क्षेत्र के लिए एक एकीकृत परस्पर निर्भर और सतत विकास ढांचे का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के लिए वन भूमि पर आवास निर्माण के लिए एक बीघा तक भूमि देने की अनुमति वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रदान करने की मांग भी की।

चुनाव आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 2020 के एक महत्वपूर्ण प्रावधान को लागू करते हुए प्रदेश की सभी पंचायतों और नगर निकायों की संरचना, वर्गीकरण व सीमाओं में किसी भी प्रकार का बदलाव तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। इस संबंध में आयोग द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता..........57''—

प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियां तेज़ हो गई हैं। इसी कड़ी में राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में पंचायतों और नगर निकायों की संरचना, वर्गीकरण और सीमाओं में किसी भी तरह के बदलाव पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। आयोग ने निर्देश दिया है कि चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी पंचायत या नगर पालिका की सीमाओं, वर्गीकरण या संरचना में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आयोग ने ये कदम उन स्थानीय निकायों के समय पर चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है, जिनका कार्यकाल अगले वर्ष के शुरूआत में समाप्त हो रहा है। आयोग द्वारा प्रदेश की सभी 3 हज़ार 5 सौ 77 ग्राम पंचायतों, 90 पंचायत समितियों, 11 ज़िला परिषदों और 71 नगर निकायों का परिसीमन पूरा कर अंतिम रूप से अधिसूचित किया जा चुका है। राज्य चुनाव आयोग ने 3 हज़ार 5 सौ 48 ग्राम पंचायतों व 70 स्थानीय शहरी निकायों की मतदाता सूचियां भी अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी हैं, जबकि शेष पंचायतों व स्थानीय शहरी निकायों की सूची एक और 7 दिसंबर को प्रकाशित की जाएंगी। रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला।

विक्रमादित्य सिंह

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र की 22 सड़कों के लिए 64 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। रोहड़ू में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि क्षेत्र में लगभग तीन सौ करोड़ रूपए के विकास कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने कहा कि कार्य निष्पादन में किसी भी प्रकार की अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

दैनिक भत्ता

मंत्रियों को मिलने वाले दैनिक भत्ते में प्रदेश सरकार ने बढ़ौतरी की है। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद सामान्य प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अब मंत्रियों के दैनिक भत्ते को 18 सौ से बढ़ाकर 25 सौ रूपए कर दिया गया है।

विधायकों के दैनिक भत्ते में सरकार पहले ही बढ़ौतरी कर चुकी है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान इस संबंध में संशोधन विधयेक को स्वीकृति प्रदान की गई थी।

ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल एट द रेट ए.आई.आर न्यूज़ अंडर स्कोर शिमला और यू–ट्यूब चैनल ए.आई.आर. शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं।

भूमि लीज

राज्य सरकार ने सरकारी भूमि को लीज पर देने की अवधि 99 से घटाकर 40 वर्ष कर दी है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब बिजली परियोजनाओं, पर्यटन, उद्योग व अन्य परियोजनाओं को भूमि 40 वर्ष के लिए लीज पर मिलेगी। हालांकि हिमुडा में रियायत देते हुए सरकार ने लीज की अवधि 80 वर्ष निर्धारित की है।

मनाली–लेह सड़क

प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली 4 सौ 35 किलोमीटर मनाली–लेह सड़क 20 नवंबर से आधिकारिक तौर पर वाहनों के लिए बंद कर दी जाएगी। सीमा सड़क संगठन की 70 आरसीसी ने भारी बर्फबारी की आशंका और सड़क पर ब्लैक जैसी परिस्थितियों को देखते हुए लाहौल स्पीति व कुल्लू जिला प्रशासन को पत्र भेजा है। लाहौल स्पीति जिला उपायुक्त ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अब इस सड़क को अगले वर्ष मई–जनू में बर्फ हटाने के बाद ही दोबारा यातायात के लिए खोला जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग 70

मंडी जिले में निर्माणाधीन हमीरपुर से मंडी वाया धर्मपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 70 की प्रगति और प्रभावित लोगों की शिकायतों के समाधान को लेकर मंडी में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सड़क निर्माण के दौरान घरों को हुए नुकसान के मुदद‍े को प्रमुखता से उठाया गया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता....

बैठक में विधायक अनिल शर्मा, चन्द्रशेखर, दिलीप ठाकुर तथा उपायुक्त अपूर्व देवगन उपस्थित रहे, जबकि शिमला से आरओ मोर्थ ए.के.कुशवाहा ने वर्चुअली भाग लिया। बैठक में सड़क की गुणवत्ता, कटिंग से प्रभावित घरों की सुरक्षा तथा निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। विधायकों की मांग पर 23, 24 और 25 नवम्बर को तीन चरणों में संयुक्त निरीक्षण करने का निर्णय लिया गया है। 23 नवम्बर को मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र के तहत तल्याहड़ से सीहण तक, 24 नवम्बर को अवाहदेवी से पाड़छु तक और 25 नवम्बर को पाड़छु से सीहण तक निरीक्षण टीम सभी संवेदनशील स्थानों का जायजा लेगी। निरीक्षण में संबंधित विधायक, राजस्व, लोक निर्माण, जलशक्ति और बिजली बोर्ड के अधिकारी, मॉर्थ के अधिकारी और कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। विधायकों ने बैठक में सड़क निर्आमाण के दौरान आर.ओ.डब्ल्यू के बाहर हुए घरों को नुकसान के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। इस

पर आरओ शिमला ने बताया कि कटिंग से घरों की सुरक्षा के लिए कंक्रीट ढंगे लगाने का प्रस्ताव दिल्ली भेजा जा चुका है।

बिक्रम ठाकुर

पूर्व उद्योग मंत्री व भाजपा नेता बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा मंडी में मनाए जाने वाले जश्न समारोह का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल से कोई भी वर्ग खुश नहीं है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर असफल रही है।

मुझे इस बात का बहुत दुख है कि कांग्रेस की सरकार पिछले तीन वर्षों से हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है और आज ये कहा जा रहा है कि तीन वर्ष का जश्न शीघ्र मनाया जाएगा और ये जश्न किस बात का। पूरा हिमाचल प्रदेश दुखी है। हम किसी भी वर्ग की बात करें, कोई भी वर्ग सुखी नहीं है। महिलाओं को गारंटियों के माध्यम से उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ है। नौजबानों को बोला गया कि एक वर्ष के अंदर एक लाख नौकरियां देंगे। वे उन नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। बागवान किसान दुखी हैं। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो खुश हो। कर्मचारी हर रोज आवाज उठाते हैं कि उनके हक नहीं मिल रहे। पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही, तो जश्न किस बात का।

सुर्खियां समाचार पत्रों से ....

आज समाचार पत्रों ने अलग–अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में पंचायतों के पुनर्गठन व पुनर्सीमांकन पर रोक। दैनिक जागरण के शब्द हैं राज्य निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता की धारा 2 दशमलव एक के लागू होने का दिया हवाला। पंजाब केसरी के शब्द हैं हिमाचल में नहीं बनेंगी नई पंचायतें व शहरी स्थानीय निकाय।

हिमाचल को मिले चंडीगढ़ में हिस्सा शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नॉर्थ जोन काउंसिल की बैठक में अमित शाह के सामने उठाया मुद्दा।

दैनिक भास्कर की एक खबर है प्रदेश में भूमि लीज पर लेने और संरक्षित वन क्षेत्रों में किया बड़ा बदलाव।

बिजली परियोजना लेने में निवेशकों का रूझान घटा शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है 208 मैगावाट के प्रोजेक्टों को मात्र एक ही आवेदन आया।

'अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर''

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य सरकारों से बेहतर निवेश वातावरण बनाने और विकास मानकों को आगे बढ़ाने में प्रतिस्पर्धा करने का किया आह्वान।
- प्रधानमंत्री कल 19 नवंबर को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त करेंगे जारी।

- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहाड़ी राज्यों की बढ़ती संवेदनशीलता को देखते हुए आपदा राहत नियमों की समीक्षा करने का केंद्र से किया आग्रह।
- राज्य सरकार ने सरकारी भूमि को लीज पर देने की अवधि 99 से घटाकर 40 वर्ष की।

  और
- प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली मनाली–लेह सड़क 20 नवंबर से आधिकारिक तौर पर वाहनों के लिए बंद।